आज़ादी का अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 30.01.2023 से 05.02.2023)

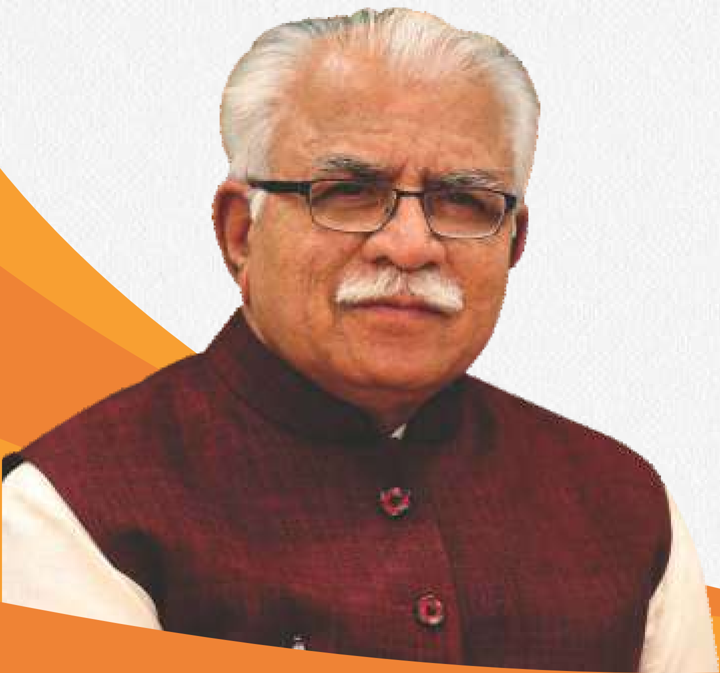

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

शेफाली वर्मा के परिवार से मुलाकात

(दिनांक 30.01.2023)

प्रभाव : अंडर–19 टी 20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान शेफाली वर्मा के रोहतक स्थित आवास पर पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके परिजनों को मिठाई खिला कर बधाई दी।

हरियाणा की बेटी शेफाली वर्मा के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अंडर–19 विश्वकप जीता है। इस

ऐतिहासिक जीत पर बेटी शेफाली और पूरी क्रिकेट टीम पर प्रदेश व देश को गर्व है।

इस मुलाकात के दौरान शेफाली वर्मा के दादा श्री संत लाल वर्मा व पिता संजीव वर्मा ने भी मुख्यमंत्री जी का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। इस अवसर पर परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि शेफाली वर्मा के नेतृत्व में पहला महिला अंडर–19 टी20 क्रिकेट विश्वकप भारत के नाम हुआ है। हरियाणा की बेटी शैफाली वर्मा के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए इंग्लैंड को हराकर विश्वकप जीता है।

प्री बजट चर्चा की बैठक का आयोजन

(दिनांक 30.01.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज गुरूग्राम में इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर से संबंधित हितधारकों के साथ वर्ष 2023–24 के आम बजट से पूर्व परामर्श (प्री बजट कंसल्टेशन) चर्चा की।

उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के वर्ष 2023–2024 के आम बजट में निर्यात, मोटे अनाज से तैयार होने वाले उत्पादों व रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाएगा। निर्यात को बढ़ावा देने से देश

में विदेशी मुद्रा आएगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर–मोटा अनाज वर्ष 2023 को देखते हुए आगामी बजट में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी उन इकाइयों को भी बढ़ावा दिया जाएगा जोकि मोटे अनाज से अपने उत्पाद तैयार करेंगी। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा नई औद्योगिक इकाइयां भी स्थापित होंगी।

मुख्यमंत्री जी ने प्री बजट कंसल्टेशन में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा रखे गए सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य की प्रगति के लिए आप सभी के अच्छे सुझावों को बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने प्रतिनिधियों को राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

हिपा के अधिकारीयों के साथ बैठक

(दिनांक 30.01.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) के कामकाज की समीक्षा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में नैतिकता व सेवा भाव की भावना को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, गुरुग्राम में नए कोर्स आरंभ करें। इन कोर्स का उद्देश्य अधिकारियों–कर्मचारियों व जनमानस के बीच अपनेपन का भाव विकसित होगा।

उन्होंने कहा कि मानव आचरण में जनसेवा के भाव को बनाए रखना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसे में प्रशासनिक कामकाज में भी नैतिकता व सेवा भाव की अनिवार्यता समय के साथ महसूस भी की जा रही है। ऐसे में नए कोर्स के माध्यम से अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशासन में नैतिक व्यवहार की मूल बातें सिखाई जाएंगी। हर कोर्स के उपरांत सभी को नैतिकता से जुड़ी किताबे भी दी जाएगी।

जॉर्जिया के राजदूत श्री आर्चिल जुलियाश्विली से शिष्टाचार मुलाकात

(दिनांक 30.01.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुरुग्राम में जॉर्जिया के राजदूत श्री आर्चिल जुलियाश्विली जी से मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा और जॉर्जिया के बीच कई विषयों पर सहयोग के बारे में चर्चा हुई।

इनमें मुख्यत: कृषि, मेडिकल ऐजुकेशन, हैल्थ सिस्टम, फार्माश्युटिकल और स्पोर्स्टस शामिल हैं। जॉर्जिया के राजदूत हरियाणा में सरकार द्वारा आई.टी क्षेत्र में किये गए सफल प्रयोग को लेकर रूचि दिखाई और कहा कि जॉर्जिया हरियाणा की इस पहल से सीखना चाहता है कि किस प्रकार आई.टी के प्रयोग से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाई जा सकती है।

मुख्यमंत्री जी ने जॉर्जिया के राजदूत को हरियाणा में की गई आई टी पहलों की जानकारी देते हुए बताया कि आई.टी के प्रयोग से सरकारी कार्यों में जहां एक ओर

साप्ताहिक सूचना पत्र

पारदर्शिता लाने में मदद मिली है वहीं दूसरी ओर सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने राजदूत को यह भी बताया कि हरियाणा में हर परिवार का पहचान पत्र अर्थात् फैमिली आई डी बनाई गई है, जोकि संभवतः पूरे विश्व में अपनी तरह का अनूठा प्रयोग है।

परिवार पहचान पत्र में परिवार के सभी सदस्यों का पूरा विवरण उपलब्ध है, जिसकी मदद से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करके उन योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को उनके घर पर पहुंचाया जा रहा है।

इसके लिए लाभार्थियों को किसी सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होती। इससे श्री आर्चिल काफी प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि जॉर्जिया इन सभी आई.टी पहलुओं को हरियाणा से सीखकर अपने देश में भी लागू करेगा, जहां की जनसंख्या हरियाणा से काफी कम है।

मुख्यमंत्री जी ने जॉर्जिया के राजदूत श्री आर्चिल को श्रीमद्भगवद् गीता भेंट करते हुए गीता सार के बारे में बताया कि किस प्रकार से युद्ध भूमि पर जब अर्जुन मानसिक द्वंद्व में फंसे थे तो भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें कर्म करने की राह दिखाते हुए अपने कर्तव्य की पालना करने की प्रेरणा दी थी।

डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो के साथ अहम बैठक

(दिनांक 30.01.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो के पुलिस उप महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। बैठक में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के विजन में राज्य सतर्कता ब्यूरो को और अधिक सशक्त करते हुए इसका नाम बदलकर भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एंटी करप्शन ब्यूरो) करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाशत नहीं किया जाएगा, चाहे वह अधिकारी, कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति ही क्यों न हों।

एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों को और अधिक सक्रियता से कार्य करना होगा, ताकि भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो सके।

मुख्यमंत्री जी ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की मंडलस्तर व जिलास्तर पर सक्रियता बढ़ाई और अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त किये थे, जिसके फलस्वरूप विजिलेंस की छापेमारी में तेजी आई और सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, प्राइवेट व्यक्तियों व इंजीनियरिंग विंग के ठेकेदारों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किये।

वर्ष 2020 बैच के एचसीएस अधिकारियों के साथ बैठक

(दिनांक 31.01.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2020 बैच के हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री जी ने सभी की निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार द्वारा आमजन के लिए चलाई जा रही जनकल्याणकारी नीतियों का पारदर्शी तरीके से जमीनीस्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि जिनके लिए यह योजनाएं बनाई गई हैं, उन पात्र लाभार्थियों को इनका त्वरित लाभ मिले। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों से सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रशासनिक दक्षता के संबंध में फीडबैक लिया। बैठक में अधिकारियों ने अपने अनुभवों को मुख्यमंत्री जी के साथ सांझा किया और आईटी से जुड़ी विभिन्न सुविधाओं के बारे में सुझाव भी दिये। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए अनेक प्रशासनिक

साप्ताहिक सूचना पत्र

सुधारों को अंजाम दिया है, ताकि प्रशासन में पारदर्शिता के साथ–साथ जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। प्रदेश सरकार मिनिमम गवर्मेंट–मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा पर कार्य कर रही है।

सुशासन के संकल्प के साथ सरकार ने अंत्योदय के उत्थान करने का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में पिछले 5 वर्षों से हर एक वर्ष को किसी न किसी संकल्प के रूप में मना रहे हैं। वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, ताकि अंत्योदय परिवार निरोगी और स्वस्थ रहें।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि क्षेत्र भ्रमण के समय लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में भी जागरूक करने का कार्य करें ताकि वे इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की नीति को अपनाये हुए है। भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाशत नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि एक अधिकारी के तौर पर आप सभी की समाज के प्रति अधिक जिम्मेवारी है, इसलिए अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी व निष्ठा से करें।

साप्ताहिक सूचना पत्र

नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड) की समीक्षा बैठक

(दिनांक 31.01.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड) के डाटा उपयोग को लेकर हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कहा कि नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड) के डाटा सत्यापन के लिए टीमें गठित कर डोर टू डोर सर्वे किया जाए। डाटा सत्यापन के साथ–साथ डेटा की सुरक्षा बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग और युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के अधिकारियों को कहा कि इस सर्वे को जल्द टीमें गठित कर कार्य को शुरू करें और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि टीमे डाटा के सत्यापन को ठीक प्रकार से करे। सरकार दिन–रात यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि लोगों का जीवन आरामदायक हो और उन्हें अपनी पारिवारिक आय बढ़ाने और उन्नती करने का अवसर मिले। ऐसी कल्याणकारी सेवाओं एवं योजनाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है ताकि निचले स्तर तक आम लोगों में उन बारे जागरूकता उत्पन्न की जा सके।

हरियाणा मंत्रिमंडल बैठक

(दिनांक 02.02.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई जोकि मुख्यत: निम्नप्रकार से हैं:–

पिंजौर (पिंजौर बद्दी खंड) में एनएच–21 ए (नया एनएच–105) पर मौजूदा लेवल क्रॉसिंग नंबर 138–बी के स्थान पर आरओबी और इसके पहुंच (एप्रोच) मार्ग के निर्माण कार्य के लिए कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के लिए अतिरिक्त लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

इस आरओबी के बन जाने से पिंजौर, अंबाला और चंडीगढ़ से औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, नालागढ़ आदि की ओर जाने वाले भारी ट्रैफिक को राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेवल क्रॉसिंग के नियमित बंद होने के कारण लगने वाले ट्रैफिकजाम से बड़ी

राहत मिलेगी। इसके अलावा, वाया डक्ट पर इस आरओबी के निर्माण के बाद स्थानीय दुकानदारों को अपना व्यावसायिक कार्यों के लिए पर्याप्त जगह मिल सकेगी और पैदल यात्री भी आरओबी के नीचे से बाजार के दूसरी तरफ जा सकेंगे। इतना ही नहीं, स्थानीय यातायात भी सुचारू रूप से चलेगा।

आयुष शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणालियों के इष्टतम विकास और प्रचार को सुनिश्चित करने के लिए आयुष विभाग को स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग से अलग करते हुए हरियाणा सरकार कार्य (आवंटन) नियम, 1974 में अलग विभाग के तौर पर शामिल किया गया है।

निदेशालय आयुष हरियाणा के तालमेल से भारत सरकार द्वारा जिला पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और जिला झज्जर के गांव देवरखाना में एक स्नातकोत्तर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार जिला हिसार, गांव मैयड़ में 50 बिस्तर का संपूर्ण आयुष अस्पताल, जिला नूंह, गांव अकेड़ा में राजकीय यूनानी कालेज व

अस्पताल तथा जिला अम्बाला, गांव चांदपुरा में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज व अस्पताल की स्थापना हेतू राज्य सरकार को सहयोग कर रही है।

हरियाणा में आयुष शिक्षा के सुदृढीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र स्थापित किया गया है। इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर प्रभावित सामंजस्य एवं तालमेल बनाए रखने और पर्याप्त विशेषज्ञता सुनिश्चित करने के लिए आयुष शिक्षा के विषय को निदेशालय आयुष हरियाणा की परिधि और जिम्मेदारियों के दायरे में लाने की आवश्यकता है। इसलिए आयुष विभाग को अलग विभाग के तौर पर शामिल किया गया है।

बैठक में विभागीय वित्तीय नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। यह वित्तीय नियम सभी सरकारी विभागों पर लागू होंगे। शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थानों और पॉवर यूटिलीटीज में ये प्रत्यायोजन उनकी अलग संस्था के

अनुसार होंगे।

वैधानिक निकायों, बोर्डों और निगमों (पॉवर यूटिलीटीज को छोड़कर) के मामले में, निविदाओं को स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 10 करोड़ रुपये तक की निविदाओं के लिए मौजूदा प्रत्यायोजन के अनुसार होगा।

10 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी, जिसमें प्रभारी मंत्री, प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष (मुख्य प्रशासक, सीईओ या एमडी, जैसा भी मामला हो) शामिल होंगे, वह कमेटी निविदाएं स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगे।

बैठक में हरियाणा राज्य वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा लिपिक वर्गीय, कार्यकारी अनुभाग एवं विविध (समूह–ग) सेवा नियम, 1998 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ये नियम हरियाणा राज्य वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा लिपिक वर्गीय, कार्यकारी एवं विविध (समूह–ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022 कहे जाएंगे।

हरियाणा राज्य वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा लिपिक वर्गीय,

साप्ताहिक सूचना पत्र

कार्यकारी अनुभाग एवं विविध (समूह–ग) सेवा नियम, 1998 में वन्य प्राणी निरीक्षक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शारीरिक मानदंड नियत नहीं है। वन्य प्राणी रक्षक की नियुक्ति में न्यूनतम शारीरिक मानदंड निर्धारित तो थे परंतु चलन वॉकिंग टेस्ट नहीं था और साथ ही महिला उम्मीदवार का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए इन नियमों में संशोधन किया गया है।संशोधनों के अनुसार, अब पुरुषों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानदंड के तहत कद 168 सेमी, छाती बिना फुलाए 79 सेमी और छाती फुलाकर 84 सेमी होनी चाहिए। महिला के लिए कद 155 सेंटीमीटर की है। साथ ही पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर वॉकिंग टेस्ट 4 घंटे में पूरा किया जाना है।

इस बैठक में सबसे अहम निर्णय शहीद कौशल कुमार रावत की पत्नी श्रीमती ममता रावत को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करना है। श्रीमती ममता

रावत को आयु सीमा में 30 मई 2014 एवं 28 सितंबर 2018 की शहीदी नीति के तहत ग्रुप–डी पदों पर असाधारण स्थिति में छूट दी गई है। श्री कौशल कुमार रावत, 14 फरवरी, 2019 को लेथपोरा, अवंतीपोरा, जिला पुलवामा (जम्मू एवं कश्मीर) में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा की हरियाणा सरकार हमेशा देश के जवानों के साथ खड़ी है। देश के लिए शहीद होने वाले मदपाव के परिवार को सरकार किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देगी ।

हरियाणा का बजट सत्र 20 फरवरी से होगा आरंभ

(दिनांक 02.02.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य का बजट सत्र 20 फरवरी, 2023 से आरंभ होगा। पिछले साल की तरह इस साल भी सदन की बैठक दो भागों में होगी। पहले भाग में राज्यपाल के अभिभाषण और उस पर चर्चा और बजट प्रस्तुत किया जाएगा जबकि दूसरे भाग में उस पर चर्चा तथा बजट को पारित किया जाएगा।

हरियाणा अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर वित्तीय स्थिति में है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में देश की चालू वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7 प्रतिशत दर्शाई गई है। जबकि हरियाणा की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 8 प्रतिशत है, जोकि राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में वित्तीय घाटे की सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत तक तय की गई है। हरियाणा पहले ही वित्तीय घाटे को इससे कम रखने में सफल रहा है। वित्त वर्ष 2021–22 का वित्तीय घाटा 2.9 प्रतिशत था। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि चालू वित्त वर्ष का घाटा भी इससे कम ही रहेगा।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट के अनुसार देश में वर्ष 2014 से अब तक प्रति व्यक्ति आय दो गुणा से अधिक होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है। जबकि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 लाख 75 हजार रुपये है। हरियाणा का आने वाला बजट हरियाणा के विकास को नई रफ्तार देगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

हरिहर नीति की बैठक में बच्चों से संवाद

(दिनांक 02.02.2023)

प्रभाव : हरिहर नीति के तहत आयोजित बैठक में बच्चों से बातचीत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकास की रोशनी से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहेगा, हमारा घर और परिवार एक ही है जिसका कोई नहीं उसके हम है, इस भावना से काम करे।

मुख्यमंत्री जी ने बच्चों से कहा कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी या जरूरत हो, तो सभी के लिए उनके घर के द्वार हमेशा खुले है। समाज में ऐसे बच्चे, जिनको अभिभावक छोड देते हैं या फिर त्याग देते हैं, ऐसे बच्चों को हरिहर नीति के तहत बाल देखरेख संस्थानों में रखकर इन बच्चों का पालन–पोषण कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन बच्चों के अभिभावकों द्वारा 5 वर्ष की आयु से पहले परित्यक्त या एक वर्ष की आयु से पहले अभिव्यक्त कर दिया गया हो तथा जिन्होंने बाल देखरेख गृहों में रहते हुए

साप्ताहिक सूचना पत्र

18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो ऐसे बच्चों को शैक्षणिक, वित्तीय सहायता और रोजगार सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण सहित मुफ्त स्कूल व उच्च शिक्षा और 25 वर्ष की आयु तक या शादी के बाद तक देखभाल, पुनर्वास और वित्तीय सहायता या शादी जो भी पहले हो, इसके अलावा पात्र लाभार्थियों को देखभाल के बाद रहने की व्यवस्था के लिए 8 हजार रुपये प्रति माह भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य में घर खरीदने के लिए एकमुश्त ब्याज मुक्त ऋण सुविधा दी जा रही है।

इस नीति के तहत बच्चों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दर्जा प्रदान कर रही है। इस अवसर पर बच्चों ने मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिह्न भेंट किया और मुख्यमंत्री जी ने सभी बच्चों को सम्मानित भी किया।

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान

(दिनांक 02.02.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत टीबी रोग से ग्रस्त 5 मरीजों को गोद लिया और उन्हें टीबी किट प्रदान की।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के संकल्प के तहत हरियाणा को टीबी मुक्त बनाने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। इन सार्थक प्रयासों से हरियाणा–टीबी मुक्त लक्ष्य को वर्ष 2025 तक ही पूरा कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के उद्योगपतियों, प्रशासनिक अधिकारियों, शैक्षिक संस्थानों, सामाजिक संस्थाओं, गैर–सरकारी संगठनों और निर्वाचित प्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वे इस पुनीत कार्य से जुड़ें और टीबी रोगियो को गोद लेकर उन्हें पोषाहार एवं उनके परिजनों को भावनात्मक एवं सामाजिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए आगे आएं।

साप्ताहिक सूचना पत्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में 'प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरूआत की गई। इस पहल के तहत निक्षय 2.0 प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता, जांच सहायता और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संस्था निक्षय 2'0 वेब पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करके निक्षय मित्र के रूप मे शामिल होकर टी बी रोगियों की सहायता कर सकती है। पंजीकरण के बाद भोगोलिक स्थितियों के अनुसार टीबी मरीज का चयन भी कर सकती हैं। उसके बाद गोद लेकर मरीज के इलाज पर लगभग 1 वर्ष तक मासिक स्पोर्टिव डाइट के रूप में 400 से 500 रुपये की राशि से रोगी का इलाज करने में सहायता प्रदान कर सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर स्तर पर जन सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी नागरिक टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम में अपनी सहभागिता से टीबी मुक्त हरियाणा बनाने में अपेक्षित सहयोग करें। मुख्यमंत्री जी ने आशा जताई की हरियाणा प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को 2025 तक प्राप्त करने की प्रतिबद्धता में सक्षम होगा। हम सब मिलकर हरियाण प्रदेश को टीबी मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कार्य करें।

साप्ताहिक सूचना पत्र

संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 646 वीं जयंती

(दिनांक 03.02.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देगी। इसके लिए सभी काडरों में चिह्नित कर आगामी 3 माह में कोटा तय किया जाएगा।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि जिला फतेहाबाद के गांव रसूलपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि गुरु रविदास के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा, चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी, सिरसा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पर एक चेयर स्थापित की जाएगी, ताकि उनके जीवन का अध्ययन कर उनके विचारों का प्रचार– प्रसार किया जा सके।

उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद विशेष दिन है, जब संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती पर एक साथ प्रदेश में 3 स्थानों जिला यमुनानगर, गुरुग्राम और यहां नरवाना में राज्य स्तरीय

समारोह हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरू रविदास जी के नाम से पीपली के पास एक स्मारक बनाने के लिए जमीन की पहचान हो गई है, जिस पर गुरु रविदास जी के नाम से एक बड़ा स्मारक बनाया जाएगा। जहां छात्रावास भी होगा और स्कूल भी होगा।

मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जाति के लोगों को उद्योग लगाने के लिए बड़ी सहायता की घोषणा करते हुए कहा कि लघु एवं सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए जमीन खरीद पर अब 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। अभी तक 10 प्रतिशत की छूट दी जाती थी।

इसके अलावा, व्यापार करने के लिए भी जो ऋण लिया जाता है, उस पर भी ब्याज में अन्य वर्गों के मुकाबले 20

प्रतिशत की ज्यादा छूट दी जाएगी। साथ ही उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार व उद्यमिता के लिए बढ़ावा देने के लिए बैंकों के अलावा सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतू एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। इन बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग दिलाई जाएगी।

उन्होंने नरवाना में संत रविदास धर्मशाला के जीर्णोद्धार के लिए 21 लाख रुपये देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक अनुसूचित जाति की चौपाल व धर्मशालाओं की मरम्मत आदि के लिए जो भी मांग आएगी, उन मांगों को पूरा किया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार का भौतिक विकास के साथ–साथ सामाजिक एकरूपता लाने का भी काम होता है। इसके लिए हमें बिना भेदभाव के आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए

साप्ताहिक सूचना पत्र

संतों–महापुरुषों की शिक्षाओं पर समाज चले, इसके लिए सरकार ने संत–महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार–प्रसार योजना बनाई है। इस योजना के तहत सभी संतों–महापुरुषों की जयंतियों को सरकारी स्तर पर मनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वंचितों व जरूरतंदों के सिर पर छत मुहैया करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई है। अभी तक हरियाणा में इस योजना के तहत 55 हजार परिवारों को मकान दिए जा दे चुके हैं। अब राज्य सरकार द्वारा 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों का सर्वे किया जा रहा है। ऐसे सभी परिवारों को मकान बनाने के लिए भरपूर सहायता की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अटल कैंटीन की संख्या बढ़ाई जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने जींद विधानसभा क्षेत्र में 5.56 करोड़ रुपये की लागत से अटल पार्क, 5.88 करोड़ रुपये की लागत से जींद कॉलोनी में सड़कों की मरम्मत, 4.26 करोड़ रुपये की लागत से फरैन कलां में स्थापित 33केवी सब स्टेशन, 1.12 करोड़ रुपये की लागत से उचाना खुर्द में स्थापित कम्युनिटी सेंटर तथा 2.65 करोड़ रुपये की लागत से नरवाना में बने बाल भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा, 6.25 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 5 गांवों में सिंचाई के लिए पानी के पुनः उपयोग हेतू परियोजना तथा 3.29 करोड़ रुपये की लागत से बडसिकरी माइनर के जीर्णोद्धार प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की समीक्षा बैठक

(दिनांक 03.02.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा की एक ऐसी अनूठी योजना है जो देश के किसी भी राज्य में नहीं है। योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाकर स्वरोजगार प्रदान करना है ताकि वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनें। इसके लिए शीघ्र ही अंत्योदय रोजगार मेलों के चौथे चरण का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पर संबंधित सरकारी विभागों के साथ– साथ बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे और स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाएंगे।

मुख्यमंत्री जी ने बैंक प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि गरीब परिवारों के लिए नई –नई योजनाएं बनाएं। आने वाले समय में 1 लाख अंत्योदय परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाने के लिए 5 हजार करोड़ रुपये की राशि का अलग से प्रावधान किया जाएगा। हरियाणा सरकार सहकारिता में एक बड़ा बदलाव लाने के प्रस्ताव पर कार्य कर रही है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सांझा डेयरी की परिकल्पना की गई है। इसके लिए सरकार पंचायती जमीन पर डेयरी के लिए शेड लीज पर उपलब्ध करवाएगी।

बैठक में प्रदेश के लीड बैंक पंजाब नेशनल बैंक व सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों व प्राइवेट बैंकों सहित 22 बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री जी ने बैंकर्स से आग्रह किया कि वे अंत्योदय रोजगार मेलों में स्वरोजगार ऋण के लिए विभिन्न विभागों से बैंकों को भेजे गए ऋण संबंधी आवेदनों को तत्काल स्वीकृत करें ताकि लाभार्थी को समय पर ऋण मिल सके और वह समय पर स्वरोजगार शुरू कर सके।

36वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का भव्य शुभारंभ

(दिनांक 03.02.2023)

प्रभाव : भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में फरीदाबाद जिला के सूरजकुंड में 36वें सूरजकुंड अंतर–राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया।

आज से शुरू होकर यह मेला 19 फरवरी तक चलेगा। इस अवसर पर हस्तशिल्पियों व कलाकारों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ग्लोबल–इकोनॉमी के मामले में भारत विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन गया है, इसमें कला एवं शिल्पियों का अहम योगदान है।

माननीय उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी ने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत को विश्व के मानचित्र पर उज्जवल करने में इस हस्तशिल्प मेले का अहम योगदान है। उपराष्ट्रपति जी ने सूरजकुंड मेला

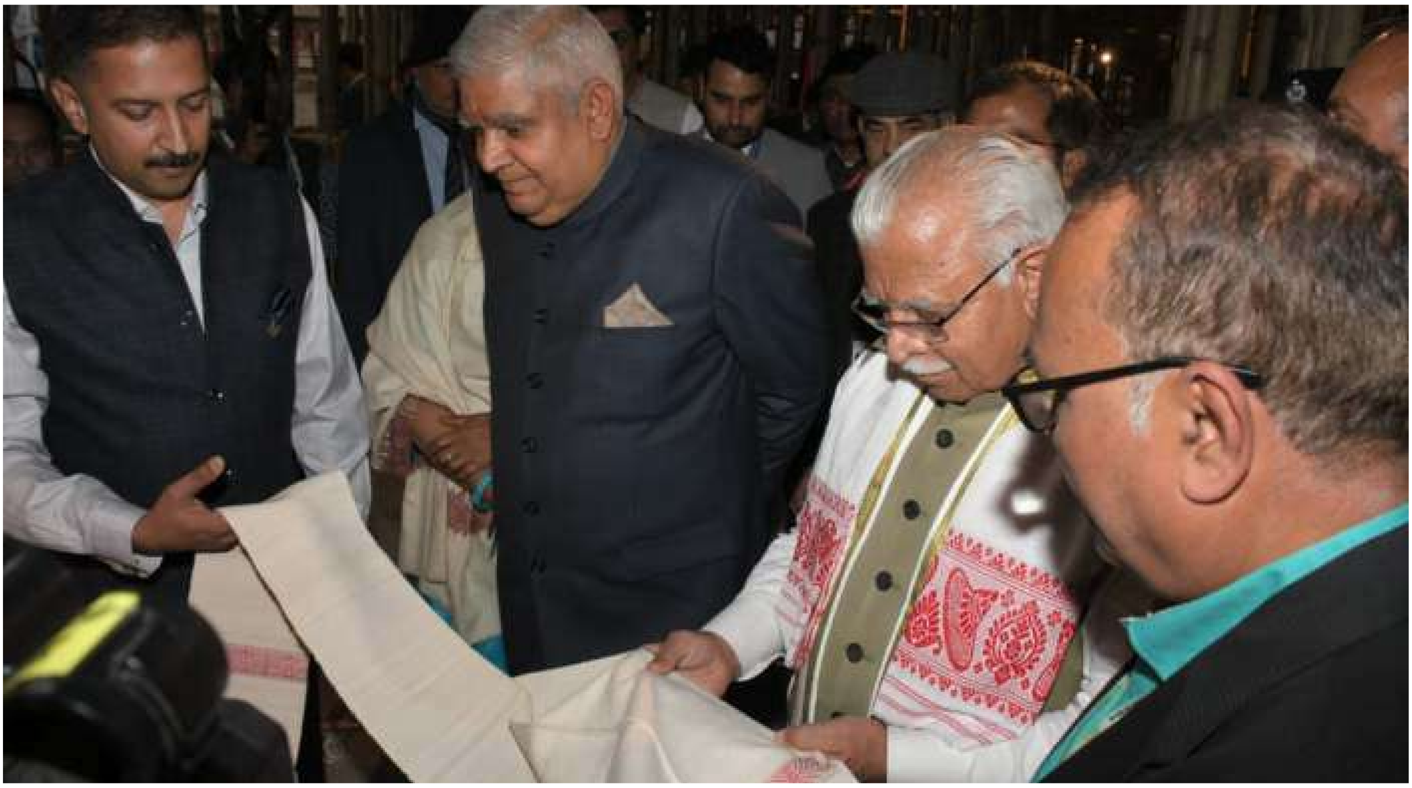

को देश की विविध संस्कृतियों एवं कलाओं का संगम करार देते हुए कहा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन देशों की इस मेले में भागीदारी एक ऐतिहासिक क्षण है।

उन्होंने भारत के उत्तर–पूर्व राज्यों की सांस्कृतिक महत्ता को देश के लिए गौरवशाली बताते हुए कहा इस मेले में पहुंचे इन राज्यों के कलाकार व शिल्पियों के रौनक से परिपूर्ण चेहरे दर्शा रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को प्रगति–पथ पर तेजी से अग्रसर किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई मुद्रा योजना, हुनर हॉट और हस्तशिल्प योजना से शिल्पकार व कलाकारों को सीधा लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि वन डिस्ट्रिक–वन प्रोडक्ट के तहत तैयार होने वाले उत्पादों की बिक्री के लिए यूनिटी मॉल कलाकारों के प्रोत्साहन में मील का पत्थर साबित होगा। एक ही स्थान पर

कलाकारों द्वारा सभी तरह के उत्पाद उपलब्ध होंगे।

उन्होने कहा कि हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है और इस विरासत को देश–दुनिया के स्तर पर ले जाने में प्रदेश सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। श्री धनखड़ जी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पर्यटन व अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है। सूरजकुंड मेला को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिलाने में मुख्यमंत्री जी का अहम प्रयास रहा है।

इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उप–राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़ का स्वागत करते हुए कहा कि यह गौरव की बात है कि इस मेले का शुभारंभ उप–राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के कर–कमलों से हो रहा है। सूरजकुण्ड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला हमारे देश की विविधता में एकता की

कड़ियों को मजबूत करने के साथ–साथ 'वसुधैव कुटुम्बकम' की अवधारणा को भी आगे बढ़ाता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस मेले में हर वर्ष एक सहभागी राष्ट्र और एक 'थीम स्टेट' होता है। इस मेले में इस वर्ष शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन सहभागी राष्ट्र हैं। इस वर्ष मेले में 25 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। भारत के 8 उत्तर–पूर्वी राज्य इस मेले के थीम स्टेट हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। ये राज्य एक साथ मिलकर एक ही मंच पर अपनी कला, हस्तशिल्प और व्यंजनों का प्रदर्शन करेंगे। यह मेला आज से शुरू होकर यह मेला 19 फरवरी तक चलेगा, जिसमें तीन वीकेंड आएंगे ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को यहां आने का मौका मिल सके।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश –विदेश के कलाकारों व शिल्पकारों की कल्पनाओं से सराबोर कलाकृतियों से सुसज्जित इस हस्तशिल्प मेले की छटा देखते ही बनती है। इस तरह के मेले शिल्पकारों को अपनी पसंद व कला के

साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा की माटी की सौंधी महक विदेशों तक पहुंची हैं। पिछले 35 वर्षों से सूरजकुंड मेला शिल्पकारों और हथकरघा कारीगरों को अपना हुनर प्रदर्शित करने का बेहतरीन मंच रहा है। यह मेला विभिन्न अंचलों की लोक–कलाओं, लोक–व्यंजनों, लोक–संगीत, लोक–नृत्यों और वेशभूषा से रू–ब–रू करवाता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन की नई अवधारणाओं पर भी काम किया है। हम फार्म टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदेश में होम स्टे स्कीम भी शुरू की गई है। अब लोग, खासकर छोटे किसान एक–दो कमरे बनाकर पर्यटकों को रख सकेंगे।

उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि देश और विदेशों से आए कलाकार और पर्यटक यहां से एक सुखद अनुभूति लेकर जाएंगे और यह अनुभूति उन्हें बार–बार हरियाणा आने के लिए प्रेरित करेगी।

आदान–प्रदान का अवसर प्रदान करते हैं। यह मेला विविधता में एकता लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन कराता है। उन्होंने कलाकारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे अपनी कलाओं को संजोए रखें और अपनी इस कला को बांटे। क्योंकि आधुनिक काल में भी इन कलाओं को बहुत पसंद किया जाता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा पिछले कई वर्षों से अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले तथा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के माध्यम से

साप्ताहिक सूचना पत्र

बीपीएल कार्ड धारकों से सीधा संवाद

(दिनांक 04.02.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज नई दिल्ली में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नए बीपीएल कार्ड धारकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने बीपीएल कार्ड बनाकर गरीब परिवारों का कल्याण किया है, अब इन परिवारों को सरकार की सभी योजनाओं का सीधा लाभ मिल पायेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार अंत्योदय परिवारों को मुख्यधारा में लाने के लिए अनेक योजनाओं को चला रही है, जिनमें रोजगार मुहैया कराने, उनके

स्वास्थ्य की देखभाल, अच्छी शिक्षा तथा आवास की सुविधा आदि शामिल हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अंत्योदय परिवारों की सुविधा के लिए अब ऑटो मोड पर बीपीएल राशन कार्ड बनाने का काम शुरू हो गया है।

आप सब लाभार्थियों के बीपीएल कार्ड भी हाल ही में बने हैं। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक आय के मापदंड के आधार पर नए बीपीएल परिवारों को जोड़ा गया है।

उन परिवारों को ऑनलाइन बीपीएल राशन कार्ड दिए जा रहे हैं, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये तक है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 29 लाख से अधिक परिवारों को नए बीपीएल कार्ड जारी किये गए हैं।

उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए चिरायु हरियाणा योजना शुरू की गई है। आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उन परिवारों को शामिल किया गया था, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार रुपये से कम थी। प्रदेश सरकार ने बी.पी.एल. के लिए यह आय सीमा बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये वार्षिक की। इससे प्रदेश में अब लगभग 20 लाख नए परिवार इस योजना में आ गए हैं। अब 28,89,036 परिवार इस योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे परिवारों को 5 लाख रुपये वार्षिक का स्वास्थ्य कवर मिल रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें रोजगार के अवसर के साथ–साथ स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। अब तक प्रदेश में तीन चरणों में 861 अंत्योदय मेलों का आयोजन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि चौथे चरण की शुरुआत जल्द ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में भी जरूरतमंद परिवारों को वरीयता दी जा रही है। ऐसे परिवारों के उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान किया गया है।

श्री जगत गुरु ब्रह्मनन्द गौशाला का वार्षिकोत्सव

(दिनांक 05.02.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज वार्षिकोत्सव के अवसर पर उपस्थित गौभक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम उठा रही है। गौवंश के चारे के लिए हर वर्ष 30 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाता है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गाय को चारा व गुड़ भी खिलाया।मुख्यमंत्री जी ने कुराना गांव के लिए कई मांगों को मंजूर किया। मुख्यमंत्री जी ने गांव की चार सड़कों को साढ़े पांच मीटर

साप्ताहिक सूचना पत्र

चौड़ा करने की मांग को मौके पर ही मंजूर किया। इसके साथ ही गांव की तरफ से मांग न होने के बावजूद भी गांव की आबादी दस हजार से अधिक होने के चलते गांव कुराना को महाग्राम योजना का लाभ देने की घोषणा की।

श्री जगत गुरु ब्रह्मानंद गौशाला कुराना के लिए मुख्यमंत्री जी ने 21 लाख रुपए का सहयोग देने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें गाय को किसान की आजीविका का साधन बनाना होगा। इसके लिए हमें देशी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत राजकीय पशुधन फार्म, हिसार में गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही है।

हरियाणा गौ–सेवा आयोग द्वारा पंचकूला में हरियाणा गोवंश अनुसंधान केन्द्र खोला गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 638 गौशालाओं में गौवंश की देखरेख में सरकारी प्रयासों के साथ–साथ सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस भी रजिस्टर्ड गौशाला को अनुदान की जरूरत है वह अपनी मांग सरल पोर्टल

साप्ताहिक सूचना पत्र

पर डाल सकती है।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री गौशाला जगमग योजना के अंतर्गत प्रदेश में 330 गौशालाओं में सोलर पावर प्लांट स्थापित किये गये हैं।

प्रदेश में गौ–पालन को प्रोत्साहित करने के लिए देशी नस्ल की गाय, जैसे कि हरयाणा, साहीवाल, बेलाही, थारपारकर, गिर आदि की 20 पशुओं की डेरी स्थापित करने पर लाभार्थियों को गाय की खरीद हेतु लिये गये बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

देशी नस्ल की 3 व 5 गायों की डेरी खोलने वाले पशुपालकों को 50 प्रतिशत अनुदान भी दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम–2015 लागू किया है, जिसके तहत गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक कारावास व एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

गौ–तस्करी करने वाले व्यक्ति को 7 वर्ष तक कैद और उपयोग किये जाने वाले वाहन को जब्त करने के अतिरिक्त 70 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त गौ हत्या व गौ–तस्करी को रोकने के लिए राज्य स्तरीय विशेष गौ संरक्षण कार्यबल का गठन किया गया है। गौ हत्या के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए फरीदाबाद व यमुनानगर में गौमांस टेस्टिंग लैब स्थापित की गई हैं।

बेसहारा गोवंश को रखने के लिए गांव नैन (पानीपत) और गांव ढंढूर (हिसार) में दो गौ अभ्यारण्य स्थापित किए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने गौशाला संचालकों से आवाहन किया कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गाय के गोबर और गोमूत्र से गोमूत्र प्राकृतिक फिनाइल, जैविक खाद, गोबर के बर्तन, प्राकृतिक पेंट, गमला, दीया, धूप, साबुन और अन्य उत्पादों के उत्पादन पर बल दें।